आकाशवाणी देहरादून (उत्तराखण्ड)

बुधवार 23.07.2025 समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- राज्य में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से गबन के मामलों की जांच के लिये एस०आई०टी गठित की जाएगी।
- मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चल रहे कार्यों को प्राथमिकता के साथ तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए।
- मुख्यमंत्री के राज्य में प्रधानमंत्री ई–बस सेवा योजना को शीघ्र शुरू करने के निर्देश, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण कार्य को समयबद्धता के साथ पूरा करने पर दिया जोर।
- कांवड़ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर, आज शिव चतुर्दशी के अवसर पर भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी यात्रा।

एस.आई.टी जांच

राज्य में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से गबन के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष जांच टीम– एस०आई०टी गठित करने के निर्देश दिए हैं। प्रथम दृष्टया जांच में कुछ मदरसों, संस्कृत विद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों द्वारा फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021–22 और 2022–23 सत्र में राज्य की कुल 92 संस्थाएं संदेह के घेरे में हैं, जिनमें से 17 संस्थानों पर गबन की पुष्टि हो चुकी है। इन मामलों में छात्रों की संख्या, पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ फर्जी पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रवृत्ति जैसी कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी जांच में संलिप्त संस्थाओं के साथ–साथ संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार ने जांच के लिए सात बिंदु तय किए हैं, जिनमें फर्जी मामलों की पहचान और एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है।

भ्रश्टाचार / गिरफ्तारी

राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में काशीपुर मंडी समिति में कार्यरत प्रभारी मंडी सचिव को सतर्कता अधिष्ठान, हल्द्वानी की टीम ने कल एक लाख बीस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। प्रभारी मंडी सचिव पर मंडी समिति में लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया के बदले प्रति लाइसेंस साठ हजार रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत की जांच के बाद सतर्कता टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए उन्हें रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्यवाही जारी है।

वाइब्रेंट विलेज

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने राज्य में वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय–सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में वाइब्रेंट विलेज योजना से संबंधित राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यों की प्रगति को लेकर केंद्र सरकार से लगातार संवाद बनाए रखा जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के चयन में पूरी गंभीरता बरती जाए और उन्हें इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता दें कि कौन से कार्य सबसे अधिक ज़रूरी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वाइब्रेंट विलेज क्षेत्रों में नागरिक प्रशासन और सैन्य तंत्र के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में आईटीबीपी, भारतीय सेना, भारत सरकार के प्रतिनिधि और राज्य सरकार के प्रमुख विभागों के अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में यह जानकारी दी गई कि वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से भेजे गए 524 प्रस्तावों में से अब तक 181 प्रस्तावों को केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 93 कार्यों के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। स्वीकृत योजनाओं में चमोली जिले के 18 में से 14, पिथौरागढ़ के 62 में से 38 और उत्तरकाशी के 13 कार्यों में से अधिकांश पर कार्य शुरू हो चुका है।

गोदाम निर्माण

केंद्र सरकार ने कहा है कि सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत ग्यारह राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसे एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि परियोजना के अंतर्गत गोदाम निर्माण के लिए 500 से अधिक समितियों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 तक निर्माण कार्य पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जल विद्युत

उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने पिछले दिनों में हुई भारी बारिश के कारण नदियों में गाद की मात्रा बढ़ने से छिबरो, खोदरी, ढकरानी, ढालीपुर और व्यासी जल विद्युत गृहों से विद्युत उत्पादन अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। जैसे ही नदियों में गाद की मात्रा कम होगी, इन परियोजनाओं से पुनः विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। निगम द्वारा शासन को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि नदियों में अत्यधिक गाद के कारण परियोजनाओं को खतरा उत्पन्न हो गया था, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

ई–बस सेवा

उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक बसों को लेकर बड़ी पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को प्रधानमंत्री ई–बस सेवा योजना को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण कार्य को भी तय समय सीमा में पूरा करने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और निर्माणाधीन बस अड्डों के कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बस अड्डों, पार्किंग स्थलों, राजकीय भवनों, गेस्ट हाउसों और पेट्रोल पंपों के पास चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाए, ताकि वाहन चालकों को आसानी से चार्जिंग की सुविधा मिल सके। उन्होंने परिवहन निगम की आय बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। बैठक के दौरान परिवहन निगम ने बताया कि देहरादून और हरिद्वार में प्रधानमंत्री ई–बस सेवा योजना के तहत 150 इलेक्ट्रिक वाहन संचालित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को सुगम, सुलभ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना से लगभग 750 नए रोजगार अवसर भी पैदा होंगे।

कांवड़ यात्रा

सावन माह की भक्ति और आस्था से ओतप्रोत विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज शिव चतुर्दशी के अवसर पर भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ यह भव्य धार्मिक आयोजन विधिवत रूप से संपन्न हो जाएगा। यात्रा के अंतिम चरण में भी हरिद्वार श्रद्धालुओं से सराबोर है और पूरा क्षेत्र शिवमय है। हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत से लेकर कल शाम तक 4 करोड़ से अधिक शिवभक्त गंगाजल भरकर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। सिर्फ कल के ही दिन में 56 लाख श्रद्धालुओं ने हरिद्वार से जल भरा। डाक कांवड़ियों की उपस्थिति ने पिछले तीन दिनों से हरिद्वार को भक्ति के रंग में पूरी तरह रंग दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल ने बताया कि भारी भीड़ के बावजूद पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए चौबीसों घंटे प्रशासन मुस्तैद रहा, और कानून एवं यातायात व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित किया गया।

कांवड़ में आमदनी

कांवड़ मेले के दौरान स्वयं सहायता समूहों ने स्टॉल लगाकर दस दिनों में 28 लाख रुपये की आमदनी अर्जित की। हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे की पहल पर महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा ये स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों पर खाद्य सामग्री, हस्तशिल्प वस्तुएँ आदि की बिक्री की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने स्वयं स्टॉलों की निगरानी करते हुए प्रतिदिन की बिक्री का रिकॉर्ड भी तैयार करवाया। ''कांवड़ मेला'' क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 18 स्वयं सहायता समूहों और सहकारिता सदस्यों द्वारा 60 से अधिक स्थानों पर पानी, चाय, नाश्ता, जूस, भोजन, फल, बेकरी उत्पाद और कांवड़ से संबंधित अन्य सामग्री के स्टॉल लगाए गए।

निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया को और तेज करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने निवेशकों की सहूलियत को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया है। श्री धामी ने शीर्ष 50 निवेशकों से अधिकारियों को नियमित संपर्क में रहने को कहा और प्रत्येक निवेशक के लिए ''निवेश मित्र'' तैनात करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में उद्योग विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा करते हुए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' प्रक्रिया, उद्यम रजिस्ट्रेशन और भूमि आवंटन की निगरानी को मजबूत करने और सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक सरल बनाने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने, युवाओं को नई नीतियों से जोड़ने और स्टार्टअप पॉलिसी के साथ यूथ इनक्यूबेशन सेंटर खोलने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय जिलों में हथकरघा, होमस्टे और कृषि आधारित लघु उद्योगों को प्राथमिकता देने तथा निर्यात नीति के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता भी जताई।

एनपीए कमी

पिछले पाँच वित्त वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों–एनपीए में महत्वपूर्ण कमी आई है। वर्ष 2021 से 2025 की अवधि के बीच एनपीए नौ दशमलव एक–एक प्रतिशत से घटकर दो दशमलव पांच–आठ प्रतिशत हो गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीए की वसूली और उसे कम करने के लिए व्यापक उपाय किए हैं।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...

उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र के समाचार को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान समाचार पत्र ने धनखड़ का इस्तीफा सेहत या सियासत शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया है। धनखड़ का विदाई समारोह नहीं। दैनिक जागरण लिखता है – जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग से मामले से जुड़ रहा धनखड़ का इस्तीफा।

त्रि–स्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 24 जुलाई को मतदान की खबर को भी सभी समाचार पत्रों ने स्थान दिया है। अमर उजाला लिखता है – 497 पोलिंग पार्टियां रवाना, प्रचार का शोर थमा। हिन्दुस्तान समाचार पत्र ने लिखता है– पहले चरण का चुनावी शोर बंद, अब डोर–टू–डोर। दैनिक जागरण ने लिखता है – पहले चरण का प्रचार थमा, 49 ब्लॉक में मतदान कल।

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं में अनिमियताएं सामने आई है। इस समाचार को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया हैं। दैनिक जागरण समाचार पत्र लिखता है – अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं में घपले की जांच करेगी एसआईटी। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है– भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेगें, 92 संस्थाएं संदेह के घेरे में, 17 में घपले की पुष्टि।

मुख्य समाचार एक बार फिर–

- राज्य में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से गबन के मामलों की जांच के लिये एस०आई०टी गठित की जाएगी।
- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों को प्राथमिकता के साथ तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए।
- मुख्यमंत्री के राज्य में प्रधानमंत्री ई–बस सेवा योजना को शीघ्र शुरू करने के निर्देश, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण कार्य को समयबद्धता के साथ पूरा करने पर दिया जोर।
- कांवड़ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर, आज शिव चतुर्दशी के अवसर पर भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी यात्रा।